RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 AUGUST TO 17 AUGUST 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 50 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

मप्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कमाए 2428 करोड़ रुपए

Page 2

ई-वे बिल की रफ्तार अगस्त में भी बरकरार

Page 3

एसबीआई ने ग्राहकों को दिलाया याद 30 सितंबर से पहले जरूर निपटा लें ये काम

Page 7

editoria!

कार्यबल में महिलाएं

आर्थिक गतिविधियों में लैंगिक संतुलन होने से आर्थिक परिणाम भी बेहतर होते हैं. कई अध्ययनों से स्पष्ट है कि यदि कार्यबल समूह में पुरुष और महिला कर्मियों की समुचित भागीदारी हो, तो निवेश, उत्पाद, परिणाम बेहतर नजर आते हैं और असफलता की गुंजाइश कम हो जाती है. लेकिन, भारत के संदर्भ में स्थिति बिल्कुल उलट है. विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम है. यहां तक कि 15 वर्ष या इससे अधिक आयु की एक तिहाई से भी कम महिलाएं कामकाजी हैं या काम की तलाश में हैं. बीते दो-तीन दशकों में महिला श्रम भागीदारी में उत्तरोत्तर गिरावट रही है. वर्ष 2005 में यह दर 26 प्रतिशत थी, जो 2019 में गिरकर 20.3 प्रतिशत पर आ गयी. महामारी ने रोजगार संकट को जहां गंभीर बना दिया है, वहीं महिलाओं के लिए रोजगार की स्थिति अधिक असहज और चिंताजनक हो गयी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही में महिला श्रम बल भागीदारी 16.1 प्रतिशत पहुंच गयी. सख्त लॉकडाउन के चलते अप्रैल-जून, 2020 तिमाही में यह रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 15.5 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी. भारत में जो महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं, उनमें ज्यादातर कम कौशल वाले कार्यों में संलग्न हैं. इनमें कृषि और कारखानों में मजदूरी करने और कुछ घरेलू सहायिकाओं के तौर पर ही रोजगार से जुड़ पाती हैं. दुर्भाग्य से इन क्षेत्रों पर महामारी की सर्वाधिक मार पड़ी है. यही वजह है कि सितंबर, 2020 में जहां पुरुषों की बेरोजगारी 12.6 प्रतिशत रही, वहीं महिलाओं में बेरोजगारी 15.8 प्रतिशत को पार कर गयी. आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2003-04 से 2010-11 की आर्थिकी की उच्च विकास अ?वधि में भी महिलाओं की रोजगार में भागीदारी दर की गिरावट जारी रही. यह दर्शाता है कि विकास का लाभ पुरुषों और महिलाओं को कभी समान रूप से नहीं मिल पाया. महामारी के कारण असंगठित क्षेत्र में हुए रोजगार नुकसान से अनेक महिलाएं रोजगार की परिधि से ही बाहर हो गयी हैं. संगठित क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी की स्थिति चिंताजनक है. चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश आदि देशों में यह स्थिति भारत से दो से तीन गुना बेहतर है. वहीं महिला श्रम बल भागीदारी दर के वैश्विक औसत (47 प्रतिशत) से तुलना करें, तो हमारी स्थिति (20 प्रतिशत) आधी भी नहीं है. इससे स्पष्ट होता है कि भारत में महिलाओं को कामकाज की स्वतंत्रता और तरक्की के लिए अभी लंबा सफर तय करना है. अगर महिलाओं की आत्मनिर्भर बढ़ेगी, तो किसी संकट का सामना करने में वे स्वयं सक्षम होंगी. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में अगर विवेकपूर्ण निवेश किया जाये, तो लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक विकास का सीधा रास्ता तय किया जा सकता है.

गिफ्ट, कैश-बैक वाउचर पर 18 फीसद की दर से लगेगा जीएसटी

नयी दिल्ली। एजेंसी

उपभोक्ताओं या आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए गिफ्ट वाउचर, कैश-बैक वाउचर को वस्तु अथवा सामान माना जाएगा और इनपर 18 फीसद की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। बेंगलुरु की प्रीमियर सेल्स प्रमोशन प्राइवेट लि. ने एएआर की कर्नाटक पीठ के समक्ष अपील दायर कर पूछा था कि गिफ्ट वाउचर, कैश-बैक वाउचर या कई विकल्पों के साथ ई-वाउचरों की आपूर्ति पर क्या जीएसटी दर लागू होगी। आवेदक कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वाउचर का कारोबार करती है। गिफ्ट वाउचर के संदर्भ में एएआर ने कहा कि आवदेक वाउचर खरीदता और उसे अपने ग्राहकों को बेचता है, जो आगे उसे अपने ग्राहकों में वितरित करते हैं। वहीं ग्राहक आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के समय अपने भुगतान की

प्रतिबद्धता इन वाउचरों से करते हैं।

ऐसे में आवेदक को उनकी आपूर्ति के समय ये गिफ्ट वाउचर 'मुद्रा का स्वरूप नहीं होते हैं। जहां तक कैश-बैक या विभिन्न विकल्प वाले ई-वाउचर का सवाल है, एएआर ने निष्कर्ष दिया है कि ये वाउचर आपूर्ति के समय इन्हें 'मुद्रा की परिभाषा के तहत नहीं माना जा सकता, लेकिन किसी वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करते समय ये पैसे का 'स्वरूप ले लेते हैं। एएआर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि वाउचर की आपूर्ति वस्तुओं की तरह करयोग्य है और इनपर 18 फीसद जीएसटी लगेगा।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि एएआर ने व्यवस्था दी है कि ई-वाउचर की आपूर्ति पर वस्तुओं की तरह 18 फीसद कर लगेगा। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि ऐसे वाउचर से क्या सामान खरीदा गया है। इसके अलावा एएआर ने जीएसटी नियमों में वर्णित आपूर्ति-संबंधित वाउचर के समय से संबंधित विशेष प्रावधानों को खारिज कर दिया है। ''इस निर्णय से सभी ई-वाउचरों पर 18 फीसद कर लगेगा।

एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना

आरबीआई की यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से होगी लागू

नई दिल्ली। एजेंसी

एटीएम में कैश नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ऐसा होता है कि आप एटीएम बूथ में जाते हैं और कैश नहीं मिलता। अब अक्टूबर से यह समस्या खत्म हो सकती है। आरबीआई ने एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए बैंकों पर लगाम कसने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक अब एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा।

आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा, ''एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

मशीन में समय पर डाली जाए नकदी

रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, ''इसीलिए यह निर्णय किया गया कि बैंक/व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।

10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं तो जुर्माना

आरबीआई ने कहा, ''इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है। योजना एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आएगी। जुर्माने की मात्रा के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम

व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो संबंधित एटीएम में नकदी को पूरा करता है। व्हाइट लेबल एटीएम का परिचालन गैर- बैंक इकाइयां करती हैं।बैंक व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक से जुर्माना राशि वसूल सकता है। देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम थे।

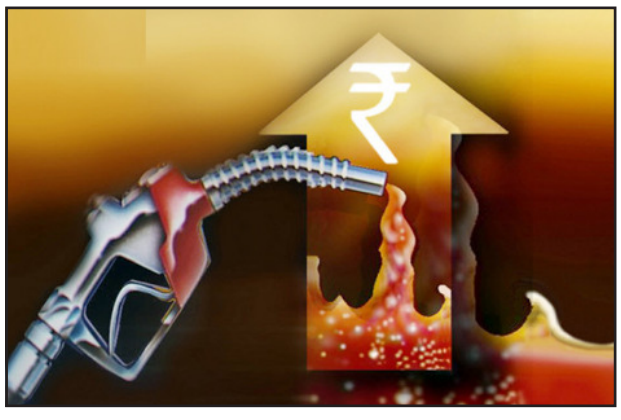

मप्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कमाए 2428 करोड़ रुपए

विधानसभा में वित्त मंत्री ने दी जानकारी

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मंहगाई अपनी चरम सीमा पर है। पिछले 6 महीने में पेट्रोल-डीजल से सरकार ने जनता से 2,429 करोड़ रुपए बसूले हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसकी जानकारी दी है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान बुधवार को कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव ने सरकार से सवाल पूछा था कि जनता से पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने कितने रुपए कमाए हैं। इसके जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पेट्रोल पर लगाए गए वेट टैक्स से सरकार ने जनवरी 2021 से जून 2021 तक 1033.76 करोड़ रुपए वसूले।

वहीं डीजल पर सरकार ने 1395.46 करोड़ रुपए जनता से बसूल किए हैं। इस तरह सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर कुल 2,429 करोड़ रुपए की वसूली की। बता दें कि राजधानी में पेट्रोल 110.20 रुपए प्रति लीटर और डीजल 98.67 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। पिछले दिनों से लगातार पेट्रोल-डीजल के दामों में बृद्धि की गई है। हालांकि बीते कुछ दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सरकार ने प्रदेश में शराब से 151 करोड़ रुपए की कमाई की है। बीते साल की बात करें तो 2020-21 में शराब पर लगे वेट टैक्स से सरकार ने जनता से 1183.58 करोड़ रुपए कमाए थे। बता दें कि सरकार इस समय पेट्रोल पर 33 प्रतिशत, डीजल पर 23 प्रतिशत और शराब पर 10 प्रतिशत टेक्स बसूलती है। वहीं रेस्टोरेंट में बिकने वाली शराब पर 18 प्रतिशत टेक्स लेती है। विधानसभा सत्र में इसकी जानकारी दी गई है।

बीएसई का 2021-22 में 60 छोटी कंपनियां को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य

कोलकाता। एजेंसी

बंबई शेयर बाजार कारोबार में मौजूदा तेजी और पात्रता मानदंड में ढील के साथ इस साल अपने एसएमई (लघु एवं मझोले उद्यम) मंच पर करीब 60 कंपनियों की सूचीबद्धता का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बीएसई के एसएमई मंच के प्रमुख अजय ठाकुर ने कहा कि लाभ के 'रिकॉर्ड' मानदंड मामले में एक वर्ष कम कर दिया गया है। इससे प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्धता में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि एसएमई को पूंजी बाजार में लाना आसान नहीं है, लेकिन कोलकाता स्थित मर्चेंट बैंकर ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड पूर्वी तथा अन्य क्षेत्रों की छोटी उन्होंने कहा कि एसएमई को पूंजी बाजार में लाना आसान नहीं है, लेकिन कोलकाता स्थित मर्चेंट बैंकर ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड पूर्वी तथा अन्य क्षेत्रों की छोटी कंपनियों को उनके मूल्य को बाजार में आंकने और धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठाकुर ने ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज की सूचीबद्धता समारोह के दौरान अलग से बातचीत में पीटीआई-भाषा से कहा, ''हमारा अनुमान है कि इस साल 60 कंपनियां सूचीबद्ध होंगी। इसमें से 50 पहले ही दस्तावेज जमा कर चुकी हैं। सालाना औसतन 30 से 40 कंपनियां सूचीबद्ध होती थी। लेकिन इस बार संख्या अधिक है। ग्रेटेक्स समेत इस मंच पर फिलहाल 343 कंपनियां हैं।''

बैंकरों ने कहा, आरबीआई का नीतिगत दरों को यथावत रखने का निर्णय उम्मीद के अनुरूप

मुंबई। एजेंसी

बैंकरों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को घोषित मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणाओं को उम्मीद के अनुरूप करार दिया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के चेयरमैन एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख राज किरण राय जी. ने एक बयान में कहा, ''आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकारों से ईंधन उत्पादों पर उच्च अप्रत्यक्ष करों में कटौती करने के लिए भी कहा।'' उन्होंने कहा, ''आरबीआई के मौद्रिक नीति को लेकर नरम रुख बनाये रखने का कदम अपेक्षित था। यह ध्यान देने योग्य है कि जून की मौद्रिक समीक्षा में नीति में नरम रुख को जारी रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति का निर्णय एकमत से था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। '' उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का 2021-22 में मुख्य मुद्रास्फीति 5.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। उसने पहले इसके 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। राय ने कहा, ''कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं, इसलिए कीमतों पर दबाव है। इस नीति में आरबीआई ने कीमतों पर दबाव कम करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा ईंधन की कीमतों में अप्रत्यक्ष कर को कम करने के लिए फिर से दबाव डाला है।'' भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने आरबीआई की नीतिगत दर को उपयोगी बताते हुए कहा कि यह 'रुख और रणनीति' के बीच का एक दम ठीक संतुलन है। खारा ने कहा, ''वृद्धि का समर्थन करने के लिए नीतिगत रुख लगातार नरम बना हुआ है। तरलता प्रबंधन के सावधानीपूर्वक सुधार की रणनीति परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) को शुरू करने की तरफ इशारा करती है।'' निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफ़सी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने कहा कि मुद्रास्फीति पर दबाव और तरलता के उच्च स्तर को देखते हुए आरबीआई ने इसे सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक समूह की अध्यक्ष शान्ति एकाम्बरम ने कहा कि आरबीआई का ध्यान वृद्धि पर बहुत अधिक है, जिसे 'शुरुआती और हिचकिचाहट वाले पुनरुद्धार' के रूप में देखा जाता है। विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के ज़रीन दारूवाला ने भी उच्च मुद्रास्फीति और पर्याप्त तरलता को देखते हुए आरबीआई के इस कदम को उपयोगी बताया।

अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की 'बायोमिथेनेशन' परियोजनाओं के लिये ब्याज सहायता योजना शुरू

नयी दिल्ली। एजेंसी

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने मंगलवार को कहा कि उसने अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने की नवोन्मेषी 'बायोमिथेनेशन' परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के साथ गठजोड़ कर कर्ज ब्याज सहायता योजना शुरू की है। 'बायोमिथेनेशन' एक जैविक क्रिया है जिसमें कार्बनिक अपशिष्टों को हवा की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बॉयोगैस में परिवर्तित करते हैं। औद्योगिक जैविक अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने की बायोमिथेनेशन परियोजनाएं आम तौर पर पूंजी गहन और अपशिष्ट की उपलब्धता समेत परिचालन लागत तथा राजस्व के हिसाब से वित्तीय रूप से संवेदनशील होती हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ''एमएनआरई ने यूएनआईडीओ और जीईएफ के साथ मिलकर नवोन्मेषी औद्योगिक जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पाद की बॉयोमिथेनेशन परियोजना के प्रदर्शन को लेकर और व्यापार मॉडल के लिये कर्ज ब्याज सहायता योजना शुरू की है...।'' इसमें कहा गया है कि ऐसी परियोजनाओं में नवोन्मेष से ऊर्जा उत्पादन में सुधार होगा और ऊर्जा उत्पादन लागत में कमी आएगी। लेकिन स्थापना के स्तर पर शुरू में परियोजना लागत बढ़ सकती है। हालांकि परियोजना के जीवन काल के दौरान परिचालन लागत में कमी आएगी आएगी और आय बढ़ेगी। इस दौरान जैविक अपशिष्ट को लेकर जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित अपशिष्टों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने वाला उपकरण भी पेश किया गया। इसे जीईएफ-एमएनआरई-यूएनआईडीओ परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह उपकरण जिला स्तर पर शहरी तथा औद्योगिक जैविक अपशिष्टों और उसके ऊर्ज उत्पादन क्षमता अनुमान को बताता है।

साल के अंत तक आ सकता है डिजिटज करेंसी का मॉडल

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकता है। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने इस बात को दोहराया कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। वह इसके विभिन्न पहलुओं मसलन दायरे, प्रौद्योगिकी, वितरण तंत्र तथा अनुमोदन की व्यवस्था पर गौर कर रहा है। इससे पहले शंकर ने 22 जुलाई को कहा था कि भारत भी चरणबद्ध तरीके से डिजिटल मुद्रा पर विचार कर रहा है। यह इसके लिए सही समय है। चीन ने पहले ही डिजिटल मुद्रा का परीक्षण के तौर पर प्रयोग शुरू किया है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व भी इसपर विचार कर रहा है। शंकर ने मौद्रिक समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''डिजिटल मुद्रा लाने की तिथि बताना मुश्किल है। हम निकट भविष्य, संभवतः इस साल के अंत तक इसका मॉडल ला सकते हैं।''

इससे पहले 22 जुलाई को शंकर ने कहा था कि इस तरह की मुद्रा आगे चलकर सभी केंद्रीय बैंकों के पास होगी। इसी संवाददाता सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक निजी डिजिटल मुद्रा को लेकर लगातार चिंतित है और उसने इस बारे में सरकार को अवगत करा दिया है। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर काफी साल से काम चल रहा है। इस दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी मसलन बिटकॉइन काफी लोकप्रिय हुई है, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है।

रेडी-टू-कुक इडली, डोसा, दलिया मिक्स पर कितने फीसदी GST? हो गया फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

पावडर के रूप में बिकने वाले रेडी टू कुक डोसा, इडली, दलिया मिक्स जैसी खाद्य वस्तुओं आदि पर 18 प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा। हालांकि, बैटर के रूप में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत होगी। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। कृष्णा भवन फूड्स एंड स्वीट्स ने एएआर की तमिलनाडु पीठ में एक याचिका दी थी जिसमें किसी ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले बाजरा, ज्वार, रागी और मल्टीग्रेन दलिया मिक्स जैसे 49 उत्पादों पर लागू जीएसटी दर को लेकर फैसला सुनाने की अपील की गई थी। एएआर ने कहा कि कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद चूर्ण के रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। एएआर ने कहा, 'डोसा मिक्स और इडली मिक्स को पैक करके मिक्स के रूप में बेचा जाता है जिसे पानी/उबले हुए पानी/दही के साथ मिलाकर घोल बनाया जाता है और जो उत्पाद बेचा जाता है वह चूर्ण होता है, बैटर नहीं। वे सभी 49 उत्पाद जिनके लिए फैसला सुनाने की मांग गई है, सीटीएच 2106 के तहत वर्गीकृत हैं और उन पर लागू होने वाली दर नौ प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और नौ प्रतिशत राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) है।'

ई-वे बिल की रफ्तार अगस्त में भी बरकरार, रोजाना औसतन साढ़े 19 लाख बिल जनरेट

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना की दूसरी लहर के बाद अलग-अलग राज्यों में हुए अनलॉक के बाद कारोबारी गतिविधियों में आई तेजी अगस्त महीने में भी जारी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के 8 दिनों में रोजाना औसतन साढ़े 19 लाख ई-वे बिल जनरेट किए जा चुके हैं। ये जुलाई के शुरुआती दिनों के आंकड़ों के औसत से करीब सवा फीसदी ज्यादा है। वहीं मई और जून के मुकाबले भी काफी बेहतर हैं। हालांकि पूरे महीने की बात की जाए तो अब तक के आंकड़ों का औसत पूरे जुलाई के औसत के

मुकाबले करीब 6 फीसदी कम है लेकिन जानकारों का मानना है कि ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में और रफ्तार आ सकती है जिससे ये कमी भी पूरी हो जाएगी।

एक हफ्ते में 1.56 करोड़ ई-वे बिल जनरेट

1-8 अगस्त के हफ्ते में कुल 1.56 करोड़ ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं. लॉकडाउन में ढील का ही नतीजा रहा है कि मई और जून के मुकाबले जुलाई में कारोबारी गतिविधियां सुधरी हैं और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने की उम्मीद जगी है। मई करीब 4 करोड़ तो जून में 5.5 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए थे। जुलाई में ये आंकड़ा 6.42 करोड़ तक पहुंच गया था। इन गतिविधियों का असर सरकार के जीएसटी संग्रह में भी देखने को मिला। जून में हुए कारोबार का जुलाई जो टैक्स संग्रह हुआ था, उसके आंकड़े अगस्त महीने में जारी हुए थे। ये संग्रह 1.16 लाख करोड़ रुपए के करीब था।

उद्योग जगत ने कहा, 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने योग्य

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग जगत का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार की मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल होने के योग्य है। उद्योग और निर्यातकों ने यह राय जताते हुए कहा कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा कि निर्यात के लिए रणनीति तथा सभी को साथ लेकर चलने से बेहतर नतीजे हासिल होंगे। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू वित्त वर्ष के लिए 400 अरब डॉलर के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया, लेकिन यह हासिल होने योग्य है।'' परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि निर्यात से किसानों तथा देश के कारीगरों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। शक्तिवेल ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया है। इससे निर्यातक आगे बढ़कर चालू वित्त वर्ष के लिए 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे।'' प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को निर्यात लक्ष्य पर भारतीय मिशनों के प्रमुखों तथा व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के अंशधारकों के साथ चर्चा की।

नब्बे प्रतिशत लोग चाहते हैं महामारी की अवधि के लिए बुकिंग रिफंड नीति बनाए सरकार

मुंबई। एजेंसी

कोविड-19 के कारण रद्द की गई यात्रा बुकिंग के लिए रिफंड प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का आकलन करने की खातिर किए गए एक सर्वेक्षण में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार एक महामारी-विशिष्ट बुकिंग रिफंड नीति तैयार करे। ऑनलाइन मंच लोकलसर्किल द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार, 359 जिलों में 37,000 से अधिक लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं के अनुसार, कुछ ट्रैवल एजेंटों (ऑनलाइन और ऑफलाइन), एयरलाइनों के साथ-साथ होटलों ने पूरी बुकिंग राशि खोने वाले लोगों के लिए रिफंड की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। मंच के अनुसार, महामारी की दूसरी लहर के कारण यात्रा बुकिंग रद्द करने वालों में से केवल 12-13 प्रतिशत लोगों को ही समय पर रिफंड मिला। लोकलसर्किल ने कहा, 'लगभग 95 प्रतिशत नागरिकों का मानना है कि एयरलाइंस, रेलवे या होटलों की वर्तमान नीतियां उपभोक्ताओं के हित में नहीं हैं और 90 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि सरकार कोविड महामारी की इस अवधि के लिए यात्रा बुकिंग से जुड़ी एक रिफंड नीति तैयार करे।'

Income Tax:
फेसलेस एसेसमेंट के लिए आयकर विभाग ने जारी किए तीन ई-मेल आईडी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आयकर विभाग ने 'फेसलेस' या ई-आकलन योजना के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए शनिवार को करदाताओं के लिए तीन आधिकारिक ईमेल आईडी अधिसूचित किए। ई-आकलन योजना के तहत करदाता और कर अधिकारी का आमना-सामना नहीं होता। विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर एक संदेश डालते हुए कहा, 'करदाताओं के चार्टर के साथ मेल करते हुए करदाता सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, आयकर विभाग ने लंबित मामलों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस योजना के तहत समर्पित ई-मेल आईडी बनायी है।'

करदाताओं को होगी सुविधा

आयकर विभाग ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए बनायी गयी तीन अलग-अलग ईमेल आईडी के तहत शिकायतें डाली जा सकती हैं। फेसलेस आकलर प्रणाली के तहत करदाता को आयकर से जुड़े कामों के लिए विभाग के कार्यालय जाने या विभाग के किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है। एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक-आधारित प्रणाली यह पूरा काम करेगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गयी थी।

कौन से हैं तीन ई-मेल एड्रेस

सरकार की तरफ से जारी तीन ईमेल एड्रेस ये हैं- samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in, samadhan.faceless.penalty@incometax.gov.in और samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in. ईमेल एड्रेस जारी होने से टैक्सपेयर की सुविधाएं पहले की तुलना में बढ़ जाएंगी क्योंकि वे जल्द अपनी टैक्स शिकायत का निपटारा करा सकेंगे।

करदाताओं का सम्मान करेगी मोदी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को भारत का पहला टैक्सपेयर चार्टर जारी किया था। इसमें करदाताओं के अधिकार और कर्तव्य बताए गए थे। सरकार इस चार्टर के जरिये टैक्सपेयर की सेवाओं को आसान बनाने का प्रयास कर रही है।

मुंबईवासियों का नया शौक, बालकनी और छत पर तैयार कर रहे शुद्ध होम मेड शहद

मुंबई। एजेंसी

दक्षिण मुंबई के शोर-शराबे वाले इलाके में आजकल ट्रैफिक के रोज के शोरगुल से ज्यादा मधुमक्खियों (प्दहाब्ॉा) की भिनभिनाहट सुनाई देती है। भायखला में एक ड्राई फ्रूट ट्रेडर के अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल की बालकनी पर एक ऐसी कॉलोनी आकार ले रही है जो शहरों में रहने के तरीके को बदल सकती है। अप्रैल से मधुमक्खी पालन करने वाले मुर्तजा गाबाजीवाला अब पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 50 ऐसे शहरी निवासियों की बढ़ती जनजाति का हिस्सा हैं जो अपनी बालकनियों, छतों और घर के पिछवाड़े के बगीचों में मधुमक्खियों को पालते हैं और शहद निकालते हैं। कुछ लोग ऐसा शहर को हरा-भरा करने के लिए कर रहे हैं तो कुछ अपने स्वयं के भोजन आदि पैदा करने के लिए।

लॉकडाउन ने पैदा किया प्रकृति के साथ नया जुड़ाव

जब कोरोनावायरस ने लोगों को उनके घरों तक सीमित कर दिया तो कुछ लोग प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए बागवानी या बर्ड-वॉचिंग की ओर शिफ्ट हुए। मानव निर्मित पित्ती में मधुमक्खी पालन को कुछ साल पहले ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के बीच आजीविका उत्पन्न करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। अब इसका चलन शहरी इलाकों में तेज हो चला है।

'एक महीने में एक किलो शुद्ध घर का बना शहद, जो कोविड के बीच परिवार की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और पर्यावरण की मदद कर सकता है'...गाबाजीवाला को लुभाने के लिए यह मधुमक्खीपालन शुरू करने का पर्याप्त कारण था। गाबजीवाला कहते हैं, 'चीनी सीरप के साथ शहद की मिलावट करने वाले प्रमुख ब्रांडों के बारे में एक लेख पढ़ने के बाद मेरा बाजार में उपलब्ध शहद पर से विश्वास उठ गया था। मैंने महामारी के

दौरान सही खाने पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए जब मैंने सुना कि आप मधुमक्खियों को पालतू बना सकते हैं तो मैं इसे आजमाना चाहता था। अपनी आंखों के ठीक सामने शहद को अस्तित्व में आते हुए देखना आश्चर्यजनक है।'

वकील और इंजीनियर भी कर रहे मधुमक्खीपालन का कोर्स

पुणे का केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (CBRTI), सरकार के 'हनी मिशन' के तहत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करता है। पिछले दो वर्षों में मधुमक्खी पालन के पाठ्यक्रमों में वृद्धि हुई है। ण्ॅऊघ के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील पोकारे के मुताबिक, 'पहले मधुमक्खी पालन में हमारे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए साइन अप करने वालों में से ज्यादातर किसान होते थे। कोविड के कारण ऑनलाइन होने के बाद हमने पुणे, मुंबई और गोवा के वकीलों, इंजीनियरों और प्रोफेसरों को नामांकन करते देखा है।

शहरवासियों के लिए मधुमक्खी पालन की ग्रामीण कला को बदलने में मदद करने के लिए वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉ. मधुरिता गुप्ता जैसे स्वतंत्र प्रशिक्षक मौजूद हैं, जिन्होंने दिसंबर 2019 में 'बी सिटी' नामक एक प्रॉजेक्ट शुरू किया था। यह प्रॉजेक्ट शहरी क्षेत्रों में पॉलिनेटर हैबिटेट में सुधार के लिए है। वह कहती हैं, 'शुरू में जब हमने खारघर में वर्कशॉप आयोजित करना शुरू किया, तब लोग डरे हुए थे। एक बार जब उन्होंने महसूस किया कि मधुमक्खियां घर पर सुरक्षित हैं और घटती मधुमक्खी आबादी को बचाने की जरूरत के प्रति जागरुकता बढ़ी तो नवी मुंबई, ठाणे, कर्जत, पनवेल, पुणे और कोल्हापुर के लोग अपने घरों, खेतों और कारखानों में मधुमक्खी पालन में मदद के लिए आगे आने लगे।'

घर पर मधुमक्खी पालन के लिए किन चीजों की जरूरत

मानव निर्मित पित्ती में मधुमक्खी पालन एक कम रखरखाव वाली गतिविधि है। इसमें कम जगह, कुछ उपकरण, कुछ मधुमक्खियों, और एक हाइव की जरूरत होती है। हाइव लगभग एक डेस्क के दराज के आकार को हो सकता है। गुप्ता के मुताबिक, 'सिंधुदुर्ग में किसानों से लकड़ी के बक्से के साथ एक पूरी मधुमक्खी कॉलोनी खरीद सकते हैं। टॉप बॉक्स वह जगह है, जहां मधुमक्खियां शहद जमा करती हैं। बॉटम के बॉक्स में रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, अंडे, लार्वा और यंग मधुमक्खियां होती हैं।' कोई भी घर पर मधुमक्खी पालन शुरू कर सकता है। आगे कहा कि घर पर फूलों के पौधे रखना भी जरूरी नहीं है क्योंकि मधुमक्खियां नेक्टर और पराग की तलाश में 5 किमी तक की यात्रा कर सकती हैं।

रेजिडेंशियल एरिया में मधुमक्खी पालन कितना सेफ

लेकिन क्या मधुमक्खियों को आवासीय सीमा में आमंत्रित करना बुद्धिमानी है? कहीं यह आम आदमी या पड़ोसियों के लिए भयावह तो नहीं हो सकता है? गुप्ता के मुताबिक, पेड़ों से लटकते हुए आप जो छत्ते देखते हैं, वे विशाल प्रकार की मधुमक्खियों के होते हैं जैसे- एपिस डोरसाटा या एपिस फ्लोरिया। ये खतरनाक हैं। शहरी परिदृश्य में जिन प्रजातियों को पालतू बनाया जा सकता है, वे हैं एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा। ये फरार नहीं होती हैं, उनका झुंड नियंत्रित किया जा सकता है है और जब तक उकसाया नहीं जाता है, तब तक ये डंक नहीं मारतीं। हालांकि स्मोकर, वील्ड हैट और दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक गियर के साथ शहद निकालना चाहिए। मधुमक्खी के बक्से को एक खुली बालकनी या खिड़की में रखा जाना चाहिए, जिसके प्रवेश द्वार बाहर की ओर हों। याद रखें कि पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद ही मधुमक्खी पालन शुरू करें। बॉक्स को खोलने के दौरान कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने से बचें। हाइव के टॉप को प्लास्टिक शीट से कवर न करें।

कोल इंडिया का पहली तिमाही शुद्ध लाभ 52 प्रतिशत बढ़कर 3,170 करोड़ रुपये पर पहुंचा

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 52.4 प्रतिशत बढ़कर 3,169.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। परिचालन आय बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने 2,079.60 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 25,282.15 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 18,486.77 करोड़ रुपये रही थी।

चालू वित्त वर्ष में 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी का खर्च बढ़कर 21,626.48 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 16,470.64 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का कोयला उत्पादन बढ़कर 12.39 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 12.10 करोड़ टन रहा था। इसी तरह समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कच्चे कोयले का उठाव बढ़कर 16.04 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान तिमाही में 12.08 करोड़ टन था। देश के कोयले उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। कोल इंडिया ने 2023-24 तक एक अरब टन के कोयला उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोयले की निकासी, खोज और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों में 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है।

हाईकोर्ट और इरडा के निर्देश के बावजूद कोविड के एक तिहाई बीमा दावे अटके

10700 करोड़ के दावों का भुगतान नहीं हुआ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सिर्फ एक क्लिक पर बीमा क्लेम निपटाने का दावा करने वाली बीमा कंपनियां क्लेम देते समय बीमाधारकों को क्लेम देने में आनाकानी कर रही हैं। हाईकोर्ट और बीमा नियामक इरडा के निर्देश के बावजूद मौजूदा समय तक 10700 करोड़ के दावों का भुगतान नहीं हुआ है। यह कुल बीमा दावों की राशि का करीब एक तिहाई है। कोविड से जुड़े बीमा दावों की की कुल राशि करीब 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। बीमा नियामक इरडा के हिदायत की परवाह किए बगैर बीमा कंपनियां और अस्पताल क्लेम की प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय ले रहे हैं। इरडा ने बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि कोविड से जुड़े क्लेम का निपटान एक घंटे में कर दिया जाए। हालांकि, इसपर अमल करने की बजाय अस्पताल और बीमा कंपनियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के साथ बीमाधारक को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। इसकी वजह से करीब चार लाख कोविड से जुड़े बीमा दावों का निपटान नहीं हो

पाया है। इतना ही नहीं क्लेम की रफ्तार बढ़ने के साथ बीमा कंपनियों ने एक तरफ निपटान की रफ्तार सुस्त कर दी वहीं क्लेम अस्वीकार (रिजेक्ट) करने की रफ्तार बढ़ा दी है।

कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने केवल एक घंटे में बीमा सेटलमेंट करने का निर्देश दिया हुआ है। इसके बावजूद बीमा कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट करने में कई घंटे लग रहे हैं। कैशलेस बीमा सेटलमेंट की स्थिति में अस्पताल सेटलमेंट होने तक कई घंटे तक मरीज को इंतजार करवा रहे हैं। इसके लिए वह बीमा कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

दस्तावेज के नाम पर क्लेम रोक रहीं कंपनियां

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की बीमा कंपनियों से कोविड से जुड़े बीमा सेटलमेंट को लेकर बीमाधारक परेशान हैं। बीमा नियामक इरडा कई बार हिदायत दे चुका है कि क्लेम जितना जल्दी हो उसका सेटलमेंट करें और बीमाधारक को बेवजह परेशान न करें। इसके बावजूद बीमा कंपनियां क्लेम सेटलमेंट करते समय कई तरह के दस्तावेज मांग रही हैं। इतना ही नहीं कई दस्तावेज दोबारा मांगे जा रहे हैं। इससे क्लेम सेटलमेंट में देरी हो रही है।

कोविड क्लेम में दोगुना वृद्धि

क्लेम सेटलमेंट में देरी को लेकर निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसकी कई वजहें हैं। उनका कहना है कि पिछले एक साल में कोविड क्लेम में दोगुना इजाफा हुआ है, जिससे इससे जुड़े क्लेम को तय समय में निपटाने में देरी हो रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बीमा कंपनियों की ओर से अस्पतालों को यह पहले ही बताया जा चुका है कि मरीज में सुधार की गति को देखते हुए डिस्चार्ज के 24 घंटे पहले ज्यादातर दस्तावेज वह बीमा कंपनी को भेज दें। बाकी दस्तावेज डिस्चार्ज के समय भेजें। इससे कम समय लगेगा, लेकिन कई अस्पताल ऐसा नहीं कर रहे हैं।

क्लेम रिजेक्ट करने में आगे

बीमा कंपनियां क्लेम सेटलमेंट में देरी को लेकर चाहे जितनी बहानेबाजी कर लें आंकड़ें, उनकी नियत पर सवाल खड़े करते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में 361 करोड़ रुपये का 41713 क्लेम रिजेक्ट हुआ। जबकि, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से छह अगस्त तक 58,920 क्लेम बीमा कंपनियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, जिनकी राशि 464 करोड़ रुपये है।

कोरोना की तीसरी लहरः

अमेरिका व ब्रिटेन में बच्चों में बढ़ा संक्रमण, हमारे लिए खतरे का संकेत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को अधिक नुकसान होने का अनुमान है। वहीं, अमेरिका व ब्रिटेन में बच्चों में संक्रमण के मामले पहले की दो लहर की तुलना में बढ़ गए हैं, जो हमारे लिए खतरे का संकेत हो सकता है। अलबामा, अरकंसास, लुसियाना व फ्लोरिडा में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। अरकंसास के चिल्ड्रेन अस्पताल में संक्रमण से भर्ती होने वाले बच्चों की दर में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। सात नवजात आईसीयू में तो दो वेंटिलेटर पर जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। लुसियाना में जुलाई के आखिरी सप्ताह में सर्वाधिक 4232 बच्चों में संक्रमण मिला है। यहां 15 से 21 जुलाई के बीच पांच साल से कम उम्र के 66 बच्चों में वायरस मिला है। ब्रिटेन में हर दिन औसतन 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं फ्लोरिडा के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के 10,785 मामले सामने आए थे। 12 से 19 वर्ष के 11,048 बच्चों में संक्रमण मिला है। 23 से 30 जुलाई के बीच 224 बच्चों को भर्ती कराया गया है। भारत में भी पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में बच्चे अधिक संक्रमित हुए हैं। संदेह है कि वायरस इस बार बच्चों को अपना शिकार बना सकता है।

कोरोना से बच्चों को खतरा कम नहीं हुआ

अमेरिका में 2020 में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण कोरोना था। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के बाल रोग विशेषज्ञ प्रो. एडम फिन्न बताते हैं कि बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। मेरे साथी बताते हैं कि वे अस्पताल में संक्रमित बच्चों को देख रहे हैं लेकिन संख्या ज्यादा है। इससे स्पष्ट है बीमारी के मामले में ये लहर पहले की दो लहर की तुलना में थोड़ी अलग है।

बच्चों को हर हाल में लगे टीका

इंपीरियल कॉलेज लंदन की पीडियाट्रिक इंफेक्सियश डिसीज विशेषज्ञ डॉ. एलिजाबेथ व्हिटकर का कहना है कि अमेरिका व ब्रिटेन में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में संक्रमण दर बढ़ी है। इनमें अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है। ऐसे में बच्चों को हर हाल में टीका लगाना होगा।

मोटे बच्चों के लिए कठिन समय

विशेषज्ञों का कहना है कि मोटे व मधुमेह से ग्रसित बच्चों के लिए ये कठिन समय है। संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में बच्चों में पीडियाट्रिक इन्फलैमेट्री मल्टी सिस्टम सिंड्रोम (पीआईएमएस) के मामले बढ़ रहे हैं जिसका समय पर इलाज न हो तो बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है।

पीआईएमएस पीडित बच्चों को पहचानें

अमेरिका के सीडीसी की निदेशक प्रो. रोशेल वैलेंस्की के अनुसार कोरोना संक्रमण के तीन से चार सप्ताह बाद बच्चों को पीआईएमएस की चपेट में आने का खतरा रहता है। बच्चे को कई दिन तक तेज बुखार, पेट में दर्द, डायरिया, उल्टी, त्वचा पर चकत्ते लाल आंखें व हाथ-पैर का ठंडा होने जैसे लक्षण दिखते हैं।

स्टडी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी

कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की मिक्सिंग में एक कदम और आगे बढ़ा भारत

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस के दो टीकों की मिक्सिंग पर भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्सिंग पर स्टडी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल करने की जिम्मेदारी वेल्लोर के क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज को मिली है। खबर के मुताबिक, केंद्रीय दवा नियामक की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 29 जुलाई को ही इस स्टडी को कराए जाने के लिए सुझाव दिया था। बैठक के दौरान एक्सपर्ट कमेटी ने सीएमसी, वेल्लोर को चौथे फेज के क्लिनिकल ट्रायल किए जाने की मंजूरी देने का सुझाव दिया। इस ट्रायल में 300 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर कोविड-19 की कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्सिंग के प्रभाव जांचे जाएंगे। इस स्टडी का मकसद यह जानना है कि क्या किसी व्यक्ति के पूर्ण टीकाकरण के लिए उसे एक खुराक कोवैक्सीन और दूसरी खुराकी कोविशील्ड की दी जा सकती है। यह प्रस्तावित स्टडी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी (घ्ण्ईं) द्वारा की गई स्टडी से अलग है। आईसीएमआर ने उत्तर प्रदेश के उन लोगों पर शोध किया था, जिन्हें गलती से दो अलग-अलग कोरोना रोधी टीकों की खुराक दे दी गई थी। इस स्टडी के आधार पर आईसीएमआर ने कहा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिलाकर दिए जाने से बेहतर परिणाम दिखे हैं और इससे कोविड-19 के खिलाफ अच्छी इम्यूनिटी भी बनी है। यह स्टडी मई और जून के बीच उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों पर की गई।

संसद में सरकार ने क्या कहा था

तीन अगस्त को सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस रोधी टीकों की दोनों खुराक मिलाने के बारे में अब तक कोई सिफारिश नहीं की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 रोधी टीके हाल में विकसित किए गए हैं। विभिन्न टीकों को मिलाने और मिश्रित टीकों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण तथा अध्ययन शुरुआती अवस्था में हैं।

रिलायंस का दांव, अमेरिका की कंपनी में निवेश का किया ऐलान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सब्सिडरी कंपनी ने अमेरिका की कंपनी अंबरी इंक में दांव लगाया है। जानकारी के मुताबिक आरआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (आरएनईएसएल) 14 करोड़ 40 लाख डॉलर के निवेश करेगी। इसके तहत अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित अंबरी इंक के 4 करोड़ 23 लाख शेयर्स को रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड 5 करोड़ डॉलर में खरीदेगी। इससे रिलायंस का सोलर एनर्जी सेक्टर में दबदबा बढ़ेगा। बता दें कि अंबरी इंक के पास 4 से 24 घंटे तक काम करने वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का पेटेंट है।

क्या है फायदाः ग्रिड स्केल की 'स्टेशनरी स्टोरेज एप्लिकेशन' में इस्तेमाल होने वाली लीथियम-आयन बैटरी से जुड़ी लागत, सुरक्षा और लंबे समय तक न चलने जैसी समस्याओं से अंबरी की तकनीक छुटकारा दिला सकती है। इससे अक्षय ऊर्जा को आसानी से ग्रिड सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। आरएनईएसएल और अंबरी भारत में बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। यह रिलायंस की ग्रीन ऊर्जा इनीशियेटिव की लागत कम करने में मददगार होगा।

अंबरी 10 मेगावाट से लेकर 2 गीगावाट तक की 'एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स' की परियोजनाओं को पूरा कर सकता है। कंपनी कैल्शियम और एंटीमनी इलेक्ट्रोड-बेस्ड सेल्स और कंटेनर सिस्टम बनाएगी, जो लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में किफायती होगा। यह सिस्टम वातावरण के अनुकूल, अधिक सुरक्षित और करीब 20 वर्षों तक चल सकेगा। अंबरी सिस्टम उच्च-उपयोग वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त होगा। ऐसे उपयोगकर्ता जो दिन के समय सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे और शाम और सुबह के पीक लोड समय सिस्टम से ऊर्जा ले सकेंगे। कंपनी 2023 के बाद इसका कॉमर्शियल संचालन शुरू करेगी।

शालीमार प्रोडक्शंस लॉन्च करेगी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म 'एनजॉयमैक्स' - तिलोक कोठारी

शालीमार प्रोडक्शंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तिलोक कोठारी ने घोषणा की है कि कंपनी जल्द ही अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म - 'एनजॉयमैक्स' लॉन्च करेगी। इस मंच के माध्यम से, शालीमार विभिन्न प्रकार के परिवार के अनुकूल मुख्यधारा और क्षेत्रीय मीडिया सामग्री को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता है। कंपनी के पास सुरक्षित सामग्री वितरण के लिए एक मंच के रूप में NJOYMAX के लिए रोमांचक योजनाएं हैं और साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सीधे अनुभव के लिए ऑफ-बीट, बहुभाषी, पौराणिक और अनुभवात्मक मीडिया सामग्री को शामिल करने की योजना बनाई है। प्रारंभ में एप्लिकेशन केवल Android मोबाइल उपकरणों और टैबलेट पर उपलब्ध होगा। NJOYMAX के लिए एक वेब-ब्राउज़र आधारित प्लेटफ़ॉर्म का विकास भी चल रहा है और इसे Android ऐप के लॉन्च के तुरंत बाद पेश किया जाएगा। NJOYMAX ऐप आगे इस साल के अंत में ग्ध्ए पर आएगा।

NJOYMAX ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यकारी निदेशक किरण शेरगिल ने बताया की कंपनी शुरू में अपने ऐप के लिए मीडिया सामग्री के लिए विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करेगी और धीरे-धीरे अपनी सामग्री पुस्तकालय को विकसित करने की योजना बना रही है। जबकि कंपनी पुस्तकालय का विस्तार और क्यूरेट किया जा रहा है, NJOYMAX सीमित समय के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होगा। भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ओटीटी बाजार है। ओटीटी के माध्यम से वीडियो ऑन डिमांड के पारंपरिक प्लेटफॉर्म जैसे रेडियो, केबल, सिनेमा और थिएटर की जगह लेने की उम्मीद है। वर्तमान महामारी की स्थिति ने केवल व्यवधान को तेज किया है और प्रक्रिया को जल्द ही प्राप्त करने योग्य बना दिया है। आरबीएसए एडवाइजर्स के एक अध्ययन में, भारतीय ओटीटी क्षेत्र के 2030 तक कई गुना बढ़कर 12.5 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जो मौजूदा आकार 1.5 अरब डॉलर है। हम टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों से भारतीय भाषा बोलने वाली आबादी को लक्षित कर रहे हैं, जिनसे ओटीटी परिदृश्य में अगली वृद्धि की उम्मीद है। एनजॉयमैक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला है।

11 अगस्त को हरियाली तीज, शिव-पार्वती की इस मंगल मुहूर्त में करें पूजा

श्रावण के पवित्र माह में तीज का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रतिवर्ष श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। बुधवार, 11 अगस्त को हरियाली तीज है।

हरियाली तीज का यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने एवं व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। घर में सुख-शांति, समृद्धि के साथ ही पति के निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होने की मान्यता है। यहां पढ़ें शिव-पार्वती के पूजन के मंगल मुहूर्त-

हरियाली तीज 2021 पूजा के शुभ मुहूर्त-

हरियाली तीज व्रत की तारीख- बुधवार, 11 अगस्त 2021। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मंगलवार, 10 अगस्त को शाम 06.11 मिनट से शुरू होगी और 11 अगस्त 2021, बुधवार को शाम 04.56 मिनट पर समाप्त होगी।

अमृत काल में मुहूर्त- सुबह 01:52 से 03:26 तक रहेगा।

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:29 से 5.17 तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 14 से 03.07 तक।

गोधूलि बेला- शाम 23 से 06.47 तक।

निशिता काल- रात 14 से 12 अगस्त सुबह 12:25 तक।

रवि योग- 12 अगस्त सुबह 09:32 से 05:30 तक।

राहुकाल में पूजा नहीं करनी चाहिए। राहुकाल का समय- बुधवार- दोपहर 12:00 से 1:30 बजे तक रहेगा।

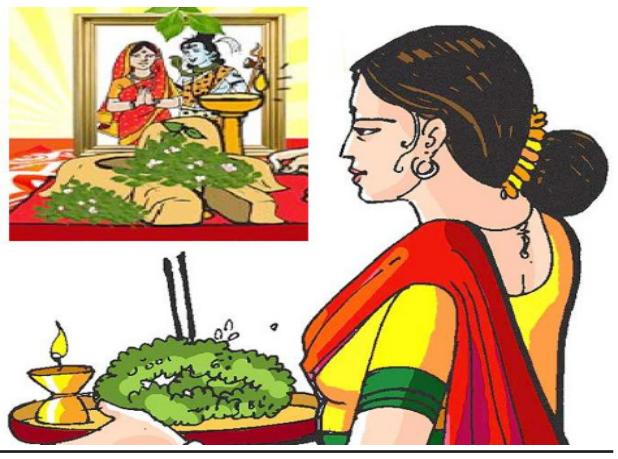

बिल्वपत्र की जड़ में होता है साक्षात लक्ष्मीजी का वास, 12 फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप

शिवजी को बिल्वपत्र, धतूरा और आंकड़ा अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिन्दू धर्म में बिल्व अथवा बेल (बिल्ला) पत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। आओ जानते हैं शिवजी को अर्पित करने के 12 फायदे।

1. कहते हैं शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है क्योंकि बिल्वपत्र की जड़ में साक्षात लक्ष्मीजी का वास होता है। इसीलिए इसके वृक्ष को श्रीवृक्ष भी कहते हैं। इसकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है।
2. इस वृक्ष की जड़ में घी, अन्न, खीर या मिष्ठान्न दान अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है और कभी भी धनाभाव नहीं रहता है।
3. इस वृक्ष की जड़ का विधिवत पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है।
4. यदि संतान सुख पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर इसका फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद इस वृक्ष के जड़ का पूजन करना चाहिए।
5. बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से समस्त तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है।
6. बिल्वपत्र की जड़ को पानी में घिसकर फिर उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों में भी यह अमृत के समान लाभकारी होती है।
7. बिल्वपत्र का सेवन, त्रिदोष यानी वात (वायु), पित्त (ताप), कफ (शीत) व पाचन क्रिया के दोषों से पैदा बीमारियों से रक्षा करता है।
8. बिल्वपत्र का सेवन त्वचा रोग और डायबिटीज के बुरे प्रभाव बढ़ने से भी रोकता है व तन के साथ मन को भी चुस्त-दुरुस्त रखता है।
9. हिन्दू धर्म में बिल्व वृक्ष के पत्र (पत्ते) शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव इसे चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं।
10. जो व्यक्ति शिव-पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित कर करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है।
11. यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। जिस घर में एक बिल्व का वृक्ष लगा होता है उस घर में लक्ष्मी का वास बतलाया गया है।
12. बिल्व पत्र को शिवजी के तीनों नेत्रों का प्रतीक भी माना जाता है। यह तीन नेत्र भूत, भविष्य और वर्तमान देखते हैं। उसी तरह महाशिवरात्रि के दिन शिवजी को बिल्व पत्र चढ़ाने से समृद्धि, शांति और शीतलता आती है।

नोट : चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति को बिल्वपत्र नहीं तोडना चाहिए।

बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र

नमो बिल्लिमने च कवचिने च
नमो वर्म्मिणे च वरूथिने च
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो
दुन्दुब्भ्याय चा हनन्याय च नमो घृश्णवे?
दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम् पापनाशनम्।
अघोर पाप संहारं बिल्व पत्रं शिवार्पणम्?
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्।
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्?
अखण्डै बिल्वपत्रैश्च पूजये शिव शंकरम्।
कोटिकन्या महादानं बिल्व पत्रं शिवार्पणम्?
गृहाण बिल्व पत्राणि सपुश्पाणि महेश्वर।
सुगन्धीनि भवानीश शिवत्वंकुसुम प्रिय।

नागपंचमी : बिलकुल नई है यह जानकारी शुभ भी होता है कालसर्प योग, जानिए कैसे

गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सुख-शांति की प्राप्ति होती है। राहु को सर्प का मुख और केतु को उसकी पूंछ माना जाता है। जब भी समस्त ग्रह इन दोनों ग्रहों के मध्य में आते हैं तो वह कालसर्प योग कहलाता है। कालसर्प योग शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। इसकी शुभता और अशुभता अन्य ग्रहों के योगों पर निर्भर करती है। ज्योतिष टीम के अनुसार जब भी कालसर्प योग में पंच महापुरुष

योग, रुचक, भद्र, मालव्य व शश योग, गज केसरी, राज सम्मान योग महाधनपति योग बनें तो व्यक्ति उन्नति करता है। जब कालसर्प योग के साथ अशुभ योग बने जैसे- ग्रहण, चाण्डाल, अशांरक, जड़त्व, नंदा, अंभोत्कम, कपर, क्रोध, पिशाच हो तो वह अनिष्टकारी होता है। ज्योतिष टीम के अनुसार ज्योतिष में 576 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं जिनमें लग्न से द्वादश स्थान तक मुख्यतः 12 प्रकार के सर्प योगों में अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, पातक, विशांत तथा शेषनाग शामिल है। कालसर्प योग दोष निवारण के लिए नागपंचमी के दिन सर्प की पूजा करना सर्वाधिक अच्छा रहता है।

श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन करते हैं ये 5 कार्य

श्रावण माह में कुछ खास दिन होते हैं जैसे सावन सोमवार, हरियाली तीज, श्रावण मास की अमावस्या आदि। उसी तरह श्रावण माह की पूर्णिमा का भी खास महत्व है। इस दिन प्रमुख रूप से 5 कार्य किए जाते हैं।

1. रक्षा बंधन का त्योहार : श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सबसे खास पर्व रक्षा बंधन का होता है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं।

2. जनेऊ बदली जाती है : इस दिन उत्तर भारत में जनेऊ बदलने का कार्य भी होता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे अबित्तम कहा जाता है। श्रावणी उपाकर्म में यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है।

3. तर्पण कर्म : इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण अर्पण भी किया जाता है। पितरों के तर्पण से उन्हें भी तृप्ति होती है। ग्रंथों में रक्षा बंधन को पुण्य प्रदायक, पाप नाशक और विष तारक या विष नाशक भी माना जाता है जो कि खराब कर्मों का नाश करता है। श्रावणी उपाकर्म में पाप-निवारण हेतु पातकों, उपपातकों और महापातकों से बचने, परद्रव्य अपहरण न करने, परनिंदा न करने, आहार-विहार का ध्यान रखने, हिंसा न करने, इंद्रियों का संयम करने एवं सदाचरण करने की प्रतिज्ञा ली जाती है।

4. स्नान और दान : इस पवित्र दिन नदी में स्नान भी किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा पर परंपरागत ढंग से तीर्थ अवगाहन, दशस्नान, हेमाद्रि संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा में दान करने का भी महत्व है। इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

5. व्रत : इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व रहता है। उत्तर और मध्य भारत में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इसे उत्तर भारत में कजरी पूनम भी कहते हैं।

6. इनकी की जाता है पूजा : इस दिन शिव, पार्वती, श्रीकृष्ण, हनुमानजी, चंद्रमा, विष्णुजी और माता लक्ष्मीजी की पूजा की जाती है।

नाग पंचमी पर घर के बाहर यह वाक्य लिखेंगे तो सर्प भय नहीं रहेगा

नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष, विषकन्या दोष, विष दोष, सर्प भय, पितृदोष आदि के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। इस दिन और भी कई उपाय करते हैं जिसके चलते सर्प भय नहीं रहता है और न ही सर्प के सपने आते हैं। आओ जानते हैं ऐसा ही एक रिवाज जो ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है।

1. नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा, वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी।
2. इन दिन मनसादेवी के पुत्र आस्तिक (आस्तीक) की पूजा की जाती है जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जनमेयज के यज्ञ से बचाया था। नाग पंचमी के दिन 'आस्तिक मुनि की दुहाई' नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और सर्प दंश का भय भी नहीं रहता है।
3. मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है जबकि कहीं-कहीं कृष्णपक्ष पंचमी को भी देवी की पूजी जाती हैं। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है।
4. मनसा देवी और आस्तिक के साथ ही माता कद्रू, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें।

देश को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने खाद्य तेलों और पॉम तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिये उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के वास्ते 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुल खाद्य तेल के आयात में पामतेल की 55 प्रतिशत की हिस्सेदारी होने की स्थिति को देखते हुए, खाद्य तेल - तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) पर राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को पाम और अन्य तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता वाले बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी सुविधाएं मिलें।

उन्होंने कहा कि किसान, दलहन उत्पादन में हासिल सफलता को तिलहन मामले में भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि पिछले छह वर्षों में दलहन का उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जिस तरह का काम हमने दलहन के मामले में किया है और पहले भी गेहूं और धान मामले में किया है, हमें खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसी तरह का प्रयास करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए आक्रामक प्रयास करना, समय की जरुरत है। किसानों से खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संकल्प के रूप में एनएमईओ-ओपी को अपनाने का आग्रह किया और कहा कि इस मिशन के तहत खाद्यतेल पारिस्थितिकी तंत्र में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक धन का निवेश किया जाएगा। मोदी ने कहा कि देश ने खाद्य तेल आयात पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि यह धन किसानों के पास जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है। ''कोरोना काल के दौरान देश ने कृषि जिसों के निर्यात के नये कीर्तिमान बनाये हैं। आज जब भारत की पहचान एक कृषि निर्यातक देश के रूप में हो रही है, तो ऐसे में खाद्य तेलों की हमारी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर होना ठीक नहीं है।'' उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र में पाम तेल की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है जहां खेती आसानी से की जा सकती है। पामतेल की खेती के बढ़ने से न केवल किसानों को बल्कि उन उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, जिन्हें सस्ती दर पर गुणवत्ता वाला खाद्यतेल मिलेगा। इसके अलावा, इससे तेल प्रसंस्करणकर्ताओं और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को लाभ होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि अधिक पैदावार और बेहतर लाभ के साथ पाम तेल की खेती से कई छोटे किसानों को फायदा होगा। तेल उद्योगों की प्रमुख संस्था, साल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के आंकड़ों के अनुसार, भारत लगभग 2.5 करोड़ टन की अपनी वार्षिक खाद्य तेल मांग का लगभग 60 प्रतिशत भाग का आयात करता है। भारत ने वर्ष 2019-20 के तेलवर्ष (नवंबर-अक्टूबर) में एक करोड़ 31 लाख टन खाद्यतेल का आयात किया। इस आयात में से ज्यादातर आयात पामतेल का किया गया था।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में वृद्धि हो रही है। सरकार ने 30 जुलाई को संसद को सूचित किया कि खुदरा बाजार में खाद्य तेलों की औसत कीमतों में इस साल जुलाई के दौरान एक साल पहले की तुलना में 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सितंबर तक कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में कमी की है और रिफाइंड पाम तेल का आयात करने की अनुमति सहित कई कदम उठाए हैं। इस कदम का स्वागत करते हुए, एसईए ने कहा कि पहले पाम तेल की खेती पर ध्यान छोटे पैमाने पर था और अब इस मिशन को नए 'अवतार' में पेश किया गया है। एसईए के अध्यक्ष, अतुल चतुर्वेदी ने कहा, 'यह देश में पाम तेल के विकास और खाद्य तेल मामले में आत्मानिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है।'' ऑयल पाम डेवलपर्स एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (ओपीडीपीए) के अध्यक्ष संजय गोयनका ने कहा, 'हालांकि हम इस मोर्चे पर विस्तृत नीति दिशानिर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, हम भारत सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं।' उन्होंने कहा, 'इस फसल के कारण आंध्र प्रदेश के किसान समुदाय के जीवन में जो बदलाव आया है उसे हमने देखा है और हम अन्य संभावना वाले राज्यों में भी इसका अनुकरण करने की उम्मीद करते हैं।' उन्होंने एक अलग बयान में कहा कि एक मजबूत और गतिशील, दीर्घकालिक नीति तंत्र इस फसल को पूरे भारत में आवश्यक बढ़ावा देगा। वर्ष 2014-15 में, सरकार ने तिलहन और तेल पाम (एनएमओओपी) पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था और इसे वर्ष 2017-18 तक जारी रखा। हालाँकि, वर्ष 2018-19 से, इस मिशन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत लागू किया जा रहा है।

भारत में टेस्ला की राह होगी आसान!

एलन मस्क की मांग पर विचार कर रही सरकार

नयी दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क को 40 फीसदी तक कम करने पर विचार कर रहा है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम ऐसा नहीं कह रहे कि आयात शुल्क में कटौती तय है लेकिन हां, इस पर चर्चा जरूर हो रही है।'

अधिकारी ने बताया कि आयात शुल्क कम करना कोई समस्या नहीं है क्योंकि देश में कई इलेक्ट्रिक वाहन आयात नहीं किए जाते हैं। लेकिन हमें इससे कुछ आर्थिक लाभ की जरूरत है। हमें घरेलू कंपनियों की चिंताओं को भी संतुलित करना होगा।' ये खबर ऐसे समय में आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने आयात शुल्क घटाने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार में मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने संसद को बताया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एलन मस्क भी कर चुके हैं मांग

दरअसल, अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री को बेताब है। एंट्री से पहले टेस्ला के सीईओ ने भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क कम करने की मांग की है। टेस्ला ने परिवहन और उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क को 60 - 100 फीसदी की मौजूदा सीमा से 40 फीसदी तक कम करने का अनुरोध किया था। वहीं, एलन मस्क ने भी ट्विटर पर ये लिखा था कि भारत में आयात शुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा है। टेस्ला की आयात शुल्क में कटौती की मांग का हुंडई समेत कई अन्य कंपनियों ने भी समर्थन किया है। बता दें कि लगभग 30 लाख वाहनों की वार्षिक बिक्री के साथ भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कार बाजार है। हालांकि, देश में बेची जाने वाली अधिकांश कारों की कीमत 20,000 डॉलर से कम है। इसमें भी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री मामूली है।

मासेराती भारत में विस्तार के लिए दूसरी, तीसरी श्रेणी के शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

इटली की कार कंपनी मासेराती अपने वाहनों की बिक्री के लिए देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन शहरों में सुपर लग्जरी ब्रांडों की बढ़ती मांग परिवर्तन लाने वाली साबित हो रही है। मासेराती ने भारत में 2015 में अपने कारोबार शुरू किया था। कंपनी ग्राहकों का अनुभव बेहतर करने के लिए अपनी बिक्री बाद सेवाओं (ऑफ्टर सेल्स) को बेहतर कर रही है। मासेराती एपीएसी के प्रमुख बोजन जानकुलोवस्की ने एक ईमेल साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा को बताया, '' मासेराती ने छोटे शहरों में मांग में बढ़ोतरी देखी है। हालांकि परंपरागत रूप से हम महानगरों में अधिक कारोबार मिलता है। भले ही इन शहरों में हमारी जमीनी उपस्थिति के मामले में विस्तार हमारे भागीदारों पर निर्भर करता है।'' उन्होंने कंपनी के भारत में विस्तार की योजना को लेकर कहा, ''भारतीय बाजार में मासेराती दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में बढ़ती मांग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत एक बहुत विविध देश है। भारत के महानगरों की संपन्नता और व्यापक पहुंच को भी हालांकि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।''

एसबीआई ने ग्राहकों को दिलाया याद

30 सितंबर से पहले जरूर निपटा लें ये काम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एक डेडलाइन के बारे में फिर से याद दिलाया है। यह डेडलाइन पैन और आधार की लिंकिंग की है। एँ ने कहा है कि आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है और ऐसा करने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। असुविधा से बचने और परेशानी रहित बैंकिंग सर्विस का लाभ उठाने के लिए दोनों डॉक्युमेंट डेडलाइन से पहले लिंक कर लें।

बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि डेडलाइन तक अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है। इसलिए किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कर लें।

लिंक न होने पर देना होगा जुर्माना

इससे पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था।

पैन और आधार की लिंकिंग तय डेडलाइन तक नहीं होने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234ए के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया।

PAN निष्क्रिय होने पर भी है जुर्माना

अगर व्यक्ति का ईं- निष्क्रिय हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल अगर आपका PAN Card निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

पैन और आधार ऑनलाइन कैसे होगा लिंक

PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर न होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है। पैन और आधार को लिंक करने के तीन तरीके मौजूद हैं।

नेटवर्क में उपरकणों के उपयोग को मान्यता देने को लेकर कड़ाई से सत्यापन की जरूरतः नीति सलाहकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार और उद्योग को साइबर हमलों को रोकने के लिए किसी संगठन के नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को मान्यता देने को लेकर बहुत कड़ाई के साथ सत्यापन समेत बेहतर गतिविधियों को अपनाने की आवश्यकता है। नीति आयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्रौद्योगिकी उत्पादों को तरजीह दी जानी चाहिए और घरेलू कंपनियों को स्वयं को उस स्तर पर ले जाने की जरूरत है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। सिन्हा ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स के साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, ''हमें संगठन के नेटवर्क में प्रत्येक उपकरण को मान्यता देने से पहले बेहद कड़ाई के साथ सत्यापन की रणनीति अपनानी होगी। साथ ही सूचना प्रणाली तक पहुंच को लेकर भी पहचान, नजर रखने की जरूरत होगी।'' उन्होंने कहा, ''संगठन के भीतर बैठकें आम बात है। विभिन्न संगठनों के बीच भी बैठके हो रही हैं। ऐसे में हमें उपकरण पंजीकरण और सॉफ्वेयर अद्यतन को लेकर स्वचालित व्यवस्था तथा खतरे का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण का लाभ उठाने की आवश्यकता है।'' सिन्हा ने कहा कि साइबर सुरक्षा को लेकर जो बेहतर गतिविधियां हैं, वह व्यापक स्तर पर अभ्यास की तरह हैं जिसे सरकार और उद्योग दोनों को बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है।

ओटिस इंडिया जेन 2रु प्राइम एलीवेटर्स के लिये करेगा ऑनलाइन ऑर्डर-बुकिंग की पेशकश

वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में ऑनलाइन ऑर्डर-बुकिंग की सुविधा देने वाली पहली प्रमुख ओईएम बनी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

ओटिस इंडिया ने एक डिजिटल पोर्टल लॉन्चट किया है, ग्राहक अब पूरी तरह ऑनलाइन तरीके से जेन2रु प्राइम एलीवेटर के लिये ऑर्डर बुक कर सकते हैं। यह कंपनी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में पहली प्रमुख ओईएम (ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चिरर) है, जिसने ऐसी डिजिटल क्षमता दी है। ओटिस वर्ल्डेवाइड कॉर्पोरेशन एलीवेटर और एस्केकलेटर के विनिर्माण, इंस्टा लेशन और सर्विस में विश्व की अग्रणी कंपनी है।

कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेघ्माल कर, ग्राहक अपने ऑर्डर को कस्टिमाइज कर सकते हैं, लाइव कोट पा सकते हैं और अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से एलीवेटर्स को बुक कर सकते हैं। बुकिंग पूरी होने के बाद, ऑनलाइन पोर्टल ऑटोमैटिक तरीके से ग्राहक को बुकिंग का कंफर्मेशन ईमेल द्वारा भेजता है। इसके बाद, ओटिस का एक सेल्सट एक्सनपर्ट ऑर्डर को फाइनलाइज करने के लिये ग्राहक से संपर्क करेगा और ऑर्डर पूरा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

ओटिस इंडिया के प्रेसिडेंट सेबी जोसेफ ने कहा, 'उद्योग का पहला पोर्टल लॉन्च् करना ओटिस में हम सभी के लिये महत्वइपूर्ण है। यहाँ एलीवेटर को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। दुनिया की तरह भारत भी 'डिजिटल-फर्स्टे' के आधार पर चलता है। इसलिये, हमने अपने ग्राहकों की जरूरतों को सर्वश्रेष्ठस तरीके से पूरा करने के लिये यह सिस्टाम बनाया- खासकर टियर-1 और टियर-2 शहरों में हमारे ग्राहकों के लिये।'

सेल्स, मार्केटिंग और स्ट्रैगटेजी के डायरेक्ट् श्रीधर राजागोपाल ने कहा, 'जेन2 प्राइम भारत के लो-राइस एलीवेटर सेगमेंट को कवर करता है। डिजिटल बुकिंग प्रोसेस से हमने अपना कवरेज और पहुँच बढ़ाई है, खासकर तेजी से बढ़ रहे टियर 2/ 3 शहरों में। हमें उत्साठह बढ़ाने वाले परिणाम मिल रहे हैं।' उन्होंहने आगे कहा, ''हम एलीवेटर उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह केवल एक बुकिंग वेबसाइट नहीं है; यह पूरी तरह से एक नया बिजनेस मॉडल है। हमारा उद्देश्यि है एलीवेटर की खरीदी को एक आम उपकरण की खरीदी की तरह आसान बनाना।'' जेन2 प्राइम का उत्पाशदन कंपनी की बेंगलुरू में स्थित विनिर्माण सुविधा में हुआ है। यह लो-राइस बिल्डिंग्सर के लिये डिजाइन किया गया एंट्री लेवल का एलीवेटर है। जेन2 प्राइम कंपनी की सबसे ज्या दा बिकने वाली फ्लैगशिप जेन2रु प्रोडक्टह फैमिली के अंतर्गत आने वाला मॉडल है।

दुबई के व्यस्त हवाईअड्डे पर यात्रियों की संख्या इस साल 40% कम

दुबई। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2021 की पहली छमाही में यात्रियों की संख्या लगभग 40 फीसदी कम हुई। दुबई हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी। यात्री संख्या में कमी की वजह कोविड-19 के ज्यादा खतरनाक वेरिएंट का प्रकोप है जिससे अब भी वैश्विक उड्डयन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। हालांकि, सीईओ पॉल ग्रिफिथ्स पूर्व-पश्चिम हवाई मार्ग के इस महत्वपूर्ण ट्रांजिट प्वाइंट (पारगमन बिंदु) को लेकर आशावादी बने हुए हैं क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप और ब्रिटेन के लिए दुबई के प्रमुख मार्ग को धीरे-धीरे फिर से खोल दिया है। ग्रिफिथ्स ने कहा, 'पिछले छह महीनों में हवाईअड्डे से 1.06 करोड़ यात्री गुजरे, यह अब भी बहुत सकारात्मक हैं। मुझे लगता है कि प्रतिबंधों में ढील के साथ इस साल का अंत संतोषजनक होगा।'

गडकरी का रिजर्व बैंक के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का ढांचागत परियोजनाओं में इस्तेमाल पर जोर

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण में भारतीय रिजर्व बैंक के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करने की खातिर नीति बनाने की वकालत करते हुए कहा कि देश को ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कम लागत वाले वित्त की जरूरत है।

उद्योग संगठन सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास भी विद्युत मंत्रालय के विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) की तरह एक वित्तीय शाखा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'देश में हमारे पास डॉलर का अधिशेष है। मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात करने का फैसला किया है कि हम एक नीति कैसे तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा हम देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर सके।'

रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 30 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.427 अरब डॉलर बढ़कर 620.576 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हाल ही में, संसद की एक समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हाल के दिनों में काफी वृद्धि हुई है और भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी भंडार की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, दीर्घकालिक सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अधिशेष धन के उपयोग की संभावना पर विचार कर सकता है। गडकरी ने कहा कि वह भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से बात कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'इसलिए हमें कुछ वित्तीय संस्थानों की जरूरत है, जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ब्याज लागत को कम कर सकते हैं।' केंद्रीय मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे को भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) मिला है, विद्युत मंत्रालय को विद्युत वित्त निगम मिला है लेकिन एनएचएआई की कोई वित्तीय शाखा नहीं है। गडकरी ने सुझाव देते हुये कहा, ''हम एक संस्थान की जरूरत है जिसमें एनएचएआई की हिस्सेदारी हो और साथ ही वित्तीय संस्थान की हिस्सेदारी भी उसमें हो। ऐसे संयुक्त उद्यम के साथ हम नीति बना सकते हैं।''

देश के सात बड़े शहरों में 2021 की पहली छमाई में आवास बिक्री 75 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के नीतिगत समर्थन तथा आवास रिण पर ब्याज दर में कमी का समर्थन पाकर देश के सात प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री वर्ष 2021 की पहली छमाई में सालाना आधार पर 75 प्रतिशत बढी गई। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लि. की भारत में आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र पर तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार मकानों की बिक्री में वृद्धि का यह रुझान आने वाली कुछ और तिमाहियों में भी जारी रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 की पहली छमाही (जनवरी से जून 2021) के दौरान सात प्रमुख शहरों में आवासीय फ्लैट की कुल बिक्री में पुणे 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा है। मुंबई की इसमें 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, वही हैदराबाद की 18 प्रतिशत और दिल्ली-एनसीआर का कुल बिक्री में 17 प्रतिशत तक हिस्सा रहा। सीबीआरई भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के चेयरमैन अंशुमान मैगज़ीन ने कहा, ''आवासीय श्रेणी ने भारत में अचल संपत्ति क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। आवासीय श्रेणी में पुनरुद्धार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई नीतिगत पहल इस मामले में महत्वपूर्ण और सराहनीय रही है।'' रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने आवास क्षेत्र में बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये स्टांप शुल्क में कटौती और संपत्ति कर में छूट देने जैसे कदम उठाये। केन्द्र सरकार के स्तर पर भी कई कदम उठाये गये साथ ही आवास रिण पर ब्याज दर कम होने से भी आवासीय बिक्री को प्रोत्साहन मिला है। आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर ने भी खरीदारों को आकर्षित करने के लिये कई तरह के प्रोत्साहन उपलब्ध कराये। इन तमाम उपायों से आवासीय क्षेत्र में वर्ष 2020 की चौथी तिमाही से ही बेहतर संकेतक मिलने लगे थे। इस दौरान तिमाही दर तिमाही आधार पर आवासीय बिक्री में 73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि का यह क्रम 2021की पहली छमाही में भी जारी रहा और आवासीय बिक्री में साल दर साल आधार पर 75 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।